भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4588
जिसका उत्तर 20 अगस्त, 2025 को दिया जाना है ।
29 श्रावण, 1947 (शक)

टोंक और सवाई माधोपुर में सामान्य सेवा केंद्र

4588. श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून 2025 तक भारतनेट परियोजना के अंतर्गत टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा से जुड़ने वाले कुल कितने गाँव हैं;

(ख) क्या सरकार के पास वर्तमान में उक्त जिलों में कार्यरत सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) की संख्या संबंधी कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) टोंक और सवाई माधोपुर जिलों के पिछड़े और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच में सुधार लाने और डिजिटल अंतर को पाटने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रमुख कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क): टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ब्रॉडबैंड सेवाएं वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तर (जीपी) तक उपलब्ध हैं। भारतनेट परियोजना के तहत दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा जून 2025 तक, राजस्थान के टोंक में 230 ग्राम पंचायत और राजस्थान के सवाई माधोपुर जिलों में 200 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है।

(ख): 30 जून, 2025 तक, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों सहित राज्य और जिलावार विवरण के साथ देश भर में सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) की कुल संख्या https://csc.gov.in/ वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ग): डिजिटल अभिगम में सुधार लाने और देश के पिछड़े और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों सहित देश भर में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों सहित देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा **भारतनेट** परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। गैर-ग्राम पंचायतों के गांवों को कनेक्टिविटी उनके संबंधित ग्राम पंचायतों से मांग के आधार पर मुहैया कराई जाएगी।

- टोंक और सवाई माधोपुर जिलों सहित देश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के सुविधारहित गांवों में **4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की परियोजना** दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के तहत टोंक (10 मोबाइल टावर) और सवाई माधोपुर (7 मोबाइल टावर) जिलों में 17 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं।
- ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2017 में **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)** शुरू किया गया था। पीएमजीदिशा योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को बुनियादी डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है, जिससे प्रति परिवार एक व्यक्ति को आवश्यक डिजिटल कौशल प्राप्त करना सुनिश्चित हो सके। देश भर में पीएमजीदिशा योजना के तहत कुल 6.39 करोड़ लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें टोंक में प्रशिक्षित 97,296 लाभार्थी और राजस्थान के सवाई माधोपुर जिलों में प्रशिक्षित 55,660 लाभार्थी शामिल हैं। यह योजना आधिकारिक तौर पर दिनांक 31.03.2024 को समाप्त हो गई है।
- भारत सरकार की एक पहल के तहत **सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)** स्थापित किए गए हैं। सीएससी एक आत्मनिर्भर और उद्यमिता मॉडल पर कार्य करते हैं। सीएससी पहल का उद्देश्य सीएससी के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को ई-सेवाएं प्रदान करना और ग्राम पंचायत स्तर तक सीएससी नेटवर्क का विस्तार करना है। सीएससी के माध्यम से 800 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनमें सरकारी सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और आधार संबंद्ध सेवाएं, विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाएं, शिक्षा, टेली-मेडिसिन, यात्रा बुकिंग, उपयोगिता भुगतान शामिल हैं।

****